

प्रेषक,

एल० एम० पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशारी अधिकारी
सम्बन्धित नगरपालिका परिषद, उत्तरांचल
(संलग्न सूची के अनुसार)

वित्त अनुभाग - 1

देहरादून : दिनांक : 19 अप्रैल, 2005

विषय : प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय वर्ष 2004-05 की समनुदेसन की रोकी गई 30 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2004-05 में 70 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा 30 प्रतिशत धनराशि उनके वित्तीय तथा संस्थागत कार्य निष्पादन से सम्बद्ध कर रोकी गई थी। आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 (ग) के अनुसार आयुक्त कुमाऊँ मण्डल की संस्तुति पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्णयानुसार मानकों के आधार पर राजस्व वृद्धि की शर्तें पूरी करने पर संलग्नक - 1 के विवरणानुसार नगर पालिका परिषदों की रोकी गई कुल धनराशि ₹0 3,26,59,000/- (₹0 तीन करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार मात्र) संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है:-

(1) स्थानीय निकायों को कुल दिये जायिक धनराशि से रोके गये 30 प्रतिशत अंश से 15 प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 के अन्तर्गत प्रस्तर 22.5 व 22.6 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर अवमुक्त किया जा रहा है।

(2) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से शहसित करने के लिये विल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संकमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का ध्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(3) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/परिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस समझ में होने वाला व्यय घालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के लेखानुदान की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को दातिपूर्ति तथा समनुदेशन -आयोजनेतर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-192-नगरपालिका/नगर निकाय-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करें से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्न :- यथोक्त।

भवदीय,

(एल० एम० पन्त)

अपर सचिव, वित्त

संख्या-406 (1)/XXVII(1)/2005 तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल।
3. निदेशक सहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. निदेशक, कोषागार वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त परिष्ठ कोषाधिकारी/कांषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/परिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
8. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9. एन० आई० सी० सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल० एम० पन्त)

अपर सचिव, वित्त

देश संख्या 406/XXVII(1)/2005, दिनांक 9 अप्रैल, 2005
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 के समनुदेशन की रोकी गई 30 प्रतिशत धनराशि
के सापेक्ष प्रस्तावित आवंटन

		(धनराशि हजार में)
क0स0	नगर पालिका परिषद का नाम	प्रस्तावित आवंटन
I	II	III
	कुमायूँ मण्डल	
		740
1	टनकपुर	248
2	भदाली	1831
3	जलपुर	1021
4	बजपुर	639
5	गदपुर	1028
6	सिद्धार्थ	468
7	बागेश्वर	5975
	योग-	
	गढ़वाल मण्डल	2433
1	उत्तरकाशी	1980
2	जोशीगढ	2233
3	धर्मोली	2860
4	नई टिहरी	937
5	नरेश्वर नगर	4888
6	मसूरी	1170
7	विक्रमनगर	2381
8	कोटद्वार	2234
9	श्रीनगर	5568
10	पीडी	26684
	योग-	32659
	महायोग-कुमायूँ+गढ़वाल	

(रुपये तीन करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार मात्र)

19/4/2005
(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त